



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 08, 1941

No. 385]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 08, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 22, अक्टूबर 2019

सं. टीएएमपी/50/2019-पीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त पीपीटी लंगरगाह और बर्थ में, कॉमन प्रयोक्ता आधार पर, एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/जलयान से जलयान अंतरण के घाटशुल्क निर्धारण के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामल संख्या टीएएमपी/50/2016-पीपीटी

परादीप पत्तन न्यास

—

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रतन सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2019 के 10वें दिन पारित)

यह मामला परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त पीपीटी लंगरगाह और बर्थ में, कॉमन प्रयोक्ता आधार पर, एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/जलयान से जलयान अंतरण के घाटशुल्क निर्धारण के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने 15 सितंबर, 2017 के अपने आदेश संख्या टीएमपी/90/2016-पीपीटी के द्वारा पीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन का अनुमोदन किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 1 नवंबर 2017 के राजपत्र संख्या 422 में अधिसूचित हुए थे। आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 को निर्धारित की गई थी। तदंतर, पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता 30 सितंबर, 2019 तक अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो बढ़ा दी गई थी।

2.2. 15 सितंबर, 2017 के उक्त आदेश के द्वारा इस प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य जहाज से छोटे पोत को पोतांतरण (कूड और पीओएल) के घाटशुल्क भी अनुमोदित किये थे।

3.1. इस आधार पर कि मौजूदा दरमान एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण के घाटशुल्क प्रभार निर्धारित नहीं करते, पीपीटी ने 5 सितंबर, 2019 के पत्र संख्या टीडी/टीएम/जीईएन-241/2282 के द्वारा परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त पीपीटी लंगरगाह और बर्थ में, कॉमन प्रयोक्ता आधार पर, एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/जलयान से जलयान अंतरण के घाटशुल्क निर्धारण के प्रस्ताव अपने 5 सितंबर 2019 के पत्र के द्वारा पीपीटी द्वारा किया गये मुख्य निवेदन इस प्रकार हैं:-

- (i) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तत्वावधान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में भारत में एलपीजी का उपयोग काफी बढ़ गया है, मुख्यतः एलपीजी व्यापन के कारण/ तेल मंत्रालय के अनुसार देश में एलपीजी व्यापन 2015 में 56.2 प्रतिशत की तुलना में 2018 में बढ़ कर 88.5 प्रतिशत हो गया है।
- (ii) स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन के सरकारी प्रयासों के कारण परिवारों से एलपीजी की मांग में बड़ोत्तरी के कारण, एलपीजी आयात वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 13.20 मिलियन टन पहुंच गया है। भारत के पूर्वी तट, ओडिशा सहित क्षेत्र में एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए सड़क टैंकरों की मूवमेंट के अतिरिक्त हल्दिया गोदी परिसर, विज्ञाग पत्तन और कामराज पत्तन के माध्यम से आयात की जा रही एलपीजी से पूरी की जाती हैं।
- (iii) एलपीजी प्रहस्तन की मात्रा और पड़ौसी पत्तनों में प्रहस्तित पोतों का औसत पार्सल आकार बढ़ता जा रहा है। हल्दिया में सीमित ड्राफ्ट व्यापार के लिए एक बहुत भारी अड़चन है कि वह बड़े पार्सल आकार के पोतों का प्रहस्तन करके आर्थिक लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसके अतिरिक्त, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने चिट्ठागांग पत्तन, बंगलादेश के माध्यम से वहां पर भी पूरी तरह भरे एलपीजी पोतों के लिए सीमित ड्राफ्ट है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एलपीजी की आपूर्ति की एक योजना बनायी है।
- (iv) पीपीटी, बर्थ के साथ-साथ और लंगरगाह में अधिक ड्राफ्ट होने के कारण, एलपीजी प्रहस्तन के लिए पत्तन की अवसंरचना का प्रयोग करने हेतु संभावित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को आकर्षित कर लाभ उठाना चाहता है।
- (v) इस संबंध में, आईओसीएल ने मुख्य पोत से छोटे पोत में, जहाज से जहाज (एसटीएस) अंतरण द्वारा एलपीजी की उतरायी द्वारा लाइट्रेज प्रचालन के लिए पीपीटी में पूर्णतः भरे हुए बड़े आकार के एलपीजी पोतों के प्रहस्तन में रुचि दिखाई है। छोटे पोतों के अतिरिक्त पोतांतरण द्वारा इस प्रकार हल्के किये गए मुख्य पोतों को भी हल्दिया, चिट्ठागांग और अन्य पत्तनों पर प्रहस्त किया जा सकता है। पीपीटी द्वारा आईओसीएल के पत्र की प्रति भी भेजी है।
- (vi) इस मामले में प्रस्तावित पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन की रूपात्मकताओं के निर्धारण के लिए 29.11.2018 को आईओसीएल के साथ चर्चा हुई। सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, भुवनेश्वर ने लंगरगाह में पोतांतरण/एसटीएस के साथ-साथ पीपीटी की उत्तरी तेल जेटी के लिए अधिसूचना/दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। पीपीटी ने उक्त अधिसूचना की एक प्रति भी भेजी है।
- (vii) पीपीटी के 2017 के मौजूदा दरमान मुख्य पोत से छोटे पोत में कूड और पीओएल के पोतांतरण के घाटशुल्क प्रभार सूचकांकन के पश्चात् विदेशी पोत के लिए 7.33 रु. प्रति एमटी और तटीय पोत के लिए 4.42 रु.

प्रति एमटी निर्धारित करते हैं। लेकिन, यह एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस के घाटशुल्क प्रभार विनिर्दिष्ट नहीं करते।

- (viii) पीपीटी द्वारा कार्गो प्रचालन को आकर्षित/प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, लंगरगाह और बर्थ में मुख्य पोत से छोटे पोतों को एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस के घाटशुल्क प्रभार उसी दर पर प्रभारित करने का प्रस्ताव किया है जो कूड/पीओएस के पोतांतरण पर लागू हैं और पोत संबंधी प्रभार मौजूदा दरमानों के अनुसार प्रभारित होगा।
- (ix) तदनुसार, 24.12.2018 को अध्यक्ष, पीपीटी के अनुमोदन से एक व्यापार परिपत्र जारी किया गया था जिसमें लंगरगाह/उत्तरी तेल जेटी पर एलपीजी/एलएनजी के ऐसे पोतांतरण की अनुमति दी गई है। पीपीटी ने व्यापार परिपत्र की प्रति भी भेजी है।

3.2. तदनुसार, पीपीटी ने उत्तरी तेल जेटी/लंगरगाह में मुख्य पोत से छोटे पोत में एलपीजी और एलएनजी पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन के लिए उसी घाटशुल्क दर को अपनाये जाने का अनुमोदन चाहा है जो उसके मौजूदा दरमान में कूड और पीओएस में यथा-उपलब्ध पोतांतरण पर लागू हैं। अर्थात् 7.33 रु. प्रतिटन विदेशी पोतों के लिए 4.42 रु. प्रति टन तटीय पोतों के लिए।

3.3. पीपीटी ने मुख्य पोत से छोटे पोत को एलपीजी और एलएनजी प्रचालन के पोतांतरण/एसटीएस के कथित घाटशुल्क के अनुमोदन का 27.05.2019 का बोर्ड का संकल्प संख्या 28/2019-20 भी प्रस्तुत किया है।

3.4. पीपीटी ने यह भी सूचित किया है पत्तन संभावित पत्तन प्रयोक्ताओं से उत्तरी तेल जेटी/लंगरगाह पर मुख्य पोत से छोटे पोत को एलपीजी और एलएनजी प्रचालन के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन आरंभ करने की चर्चा कर रहा है। लेकिन, ऐसा प्रचालन अभी आरंभ होना है।

4. पत्तन के प्रस्ताव के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

- (i) स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने की सरकार के पहल प्रयासों के कारण परिवारों में एलपीजी के उपभोग में वृद्धि होने के फलस्वरूप, भारत में एलपीजी के आयात में भी वृद्धि हुई है। परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के पास बर्थ के साथ-साथ और लंगरगाह में अधिक गहरा ड्राफ्ट होने के कारण वह चाहता है कि एलपीजी प्रहस्तन के लिए संभावित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पीपीटी की अवसंरचना का उपयोग करने को आकर्षित हों। यह एलपीजी प्रहस्तन कुछ इस प्रकार से करने की संकल्पना है कि जहां बड़े आकार के पूर्णतः भरे हुए एलपीजी पोत को पोत-से-पोत (एसटीएस) अंतरण के द्वारा लाइट्रेज प्रचालन किया जाये और मुख्य पोत से उतरायी और छोटे पोत में लदान पीपीटी में किया जाये और तत्पश्चात् हल्के पोत उन अन्य पत्तनों को प्रस्थान करें जहां ड्राफ्ट छोटे हैं। चूंकि पीपीटी के मौजूदा दरमानों में मुख्य पोत से छोटे पोत में एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन के घाटशुल्क प्रभार निर्धारित नहीं है इसलिए पीपीटी इसके लिए घाटशुल्क प्रभार निर्धारण का प्रस्ताव लेकर आया है।
- (ii) इस संबंध में, पत्तन ने अपने दरमानों में मुख्य पोत से छोटे पोत को कूड और पीओएस पोतांतरण की यथा-निर्धारित दरों को मुख्य पोत से छोटे पोतों को एलपीजी/एलएनजी पोतांतरण/एसटीएस के लिए घाटशुल्क प्रभारों के रूप में अपनाये जाने का प्रस्ताव किया है।

पीपीटी के मौजूदा दरमान, वर्ष 2017 में भाग 2.1 क्रमांक 5 यथा अनुमोदित मुख्य पोत से छोटे पोत को कूड और पीओएस पोतांतरण के घाटशुल्क प्रभार विदेशी दर 6.80 रु. प्रति एमटी और तटीय दर 4.10 रु. प्रति एमटी निर्धारित की थी। वार्षिक सूचकांकन के बारे में प्रशुल्क नीति 2015 के उपबंधों के आधार पर (जो उस समय पीपीटी पर लागू थी जब वर्ष 2017 में उनके दरमान नियत किये गए थे) मुख्य पोत से छोटे पोत को कूड और पीओएस पोतांतरण के प्रचलित घाटशुल्क प्रभार वर्ष 2017-18 के लिए 3.45% तथा वर्ष 2018-19 के लिए 4.26% के सूचकांकन कारक इस प्राधिकरण द्वारा यथा-घोषित को लागू करने के पश्चात् अब 7.33 रु. प्रति एमटी विदेशी कार्गो के लिए और 4.42 रु. प्रति एमटी तटीय कार्गो के लिए।

7.33 रु. प्रति एमटी विदेशी कार्गो के लिए और 4.42 रु. प्रति एमटी तटीय कार्गो के लिए की उक्त प्रचलित दरों को पीपीटी द्वारा मुख्य पोत से छोटे पोत में एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन के घाटशुल्क प्रभार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव किया है। पीपीटी के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

- (iii) प्रशुल्क नीति 2018 का खंड 7.6.1 से 7.6.3 अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था करते हैं कि जब कभी किसी नयी सेवा/कार्गो/उपस्कर/सुविधा के लिए विशिष्ट प्रशुल्क संबंधित पत्तन के दरमानों में उपलब्ध नहीं होता तो संबंधित महापत्तन न्यास सादृश्य कार्गो/उपस्करो/सेवाके लिए किसी अन्य महापत्तन न्यास में निर्धारित प्रशुल्क और निष्पादन मानक, यदि कोई हों, को संबंधित प्रयोक्ताओं के साथ परामर्श करके, उक्त नई सेवा/कार्गो/उपस्कर के प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

संदर्भाधीन मामले में, मुख्य पोत से छोटे पोत पर एलपीजी की एसटीएस उतरायी को बढ़ावा/ आकर्षित करने के लिए एक विपणन कार्यनीति के अनुरूप, पीपीटी ने अपने ही दरमानों में मुख्य पोत से छोटे पोत को कूड और पीओएल पोतांतरण के लिए प्रचलित दरों को अपनाने का प्रस्ताव किया है।

- (iv) पीपीटी ने सूचित किया है कि इस संबंध में उन्होंने 24 दिसंबर, 2018 को एक व्यापार परिपत्र भी जारी किया है। आज तक हमने पीपीटी द्वारा मुख्य पोत से छोटे पोत को एलपीजी की उतरायी के एसटीएस प्रभारों की उगाही के बारे में जारी व्यापार परिपत्र पर किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की है। प्रशुल्क नीति 2018 का खंड 4.4 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी प्रस्ताव या मामले में प्रयोक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है तो इस प्राधिकरण को संयुक्त बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संदर्भाधीन मामले में, पीपीटी द्वारा व्यापार परिपत्र जारी होने के पश्चात् अब तक किसी प्रयोक्ता/ प्रयोक्ता संगठन से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए, संदर्भाधीन मामले में कोई संयुक्त सुनवाई गठित नहीं की गई थी।

- (v) इस बात पर सुविचार करते हुए कि, पीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन के प्रस्तावित 7.33 रु. प्रति एमटी विदेशी कार्गो और 4.42 रु. प्रति एमटी तटीय कार्गो के घाटशुल्क प्रभार मौजूदा कूड और पीओएल के पोतांतरण के लिए निर्धारित घाटशुल्क प्रभारों का अंगीकरण पात्र ही है, और चूंकि प्रस्तावित प्रभारों को पीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और यह भी कि पीपीटी द्वारा प्रभारों की उगाही के बारे में किसी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, यह प्राधिकरण पीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन के प्रस्तावित 7.33 रु. प्रति एमटी विदेशी कार्गो और 4.42 रु. प्रति एमटी तटीय कार्गो के घाटशुल्क प्रभारों को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

- (vi) पत्तन ने एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन की प्रस्तावित घाटशुल्क दर के क्रियान्वयन से राजस्व प्रभाव का परिमाण नहीं बताया है। लेकिन, सितंबर, 2017 में पिछली बार पीपीटी के प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के दौरान 25.01 करोड़ रु. का राजस्व अंतर था जिसे तब पत्तन द्वारा अरक्षित छोड़ दिया था। एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन की अनुमोदित घाटशुल्क दर की उगाही से होने वाले अतिरिक्त राजस्व, यदि कोई हो, को राजस्व अंतर में सन्निविष्ट किये जाने की प्रत्यक्षा की जाती है।

- (vii) पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 10 अक्टूबर, 2019 के अलग से आदेश संख्या टीएमपी/90/2016-पीपीटी द्वारा 30 सितंबर, 2020 तक कर दिया गया है। पीपीटी के प्रशुल्क की आगामी समीक्षा के दौरान, पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वे दिशानिर्देशों के खंड 7.6.1 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन की घाटशुल्क दर की गणना करे। पीपीटी के मौजूदा दरमान की समीक्षा तक, अब अनुमोदित दर, पीपीटी द्वारा उगाही जानी जारी रहेगी और इसकी वैधता पीपीटी के सामान्य दरमानों की विस्तारित वैधता के साथ सह-समाप्य रहेगी।

(viii) इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यतः राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरवर्ती प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि संबंधित प्रशुलक आदेश में विशेष रूप से अन्यथा भिन्न व्यवस्था न की गई हो। तदनुसार, यह प्राधिकरण, एलपीजी/एलएनजी के पोतांतरण/एसटीएस प्रचालनों की घाटशुल्क दर की उगाही के लिए पारित आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के समाप्ति के पश्चात् उत्तरवर्ती प्रभाव से अनुमोदित करता है।

5.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमार्श के आधार पर पीपीटी के मौजूदा दरमानों में अध्याय—II में 2.1 – घाटशुल्क प्रभार के अंतर्गत घाटशुल्क अनुसूची में निम्नलिखित नया क्रमांक 5(क) जोड़ा जाना अनुमोदित किया जाता है:-

“2.1**घाटशुल्क प्रभार:**

क्र.सं.	सामान का विवरण	दर प्रति एमटी या उसका एक भाग (रु. में)	
		विदेशी दर	तटीय दर
5(क)	उत्तरी तेल जेटी/ लंगरगाह में मुख्य पोत से छोटे पोत को एलपीजी/एलएनजी का पोतांतरण/एसटीएस प्रचालन	7.33	4.42

5.2 पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान दरमानों में उक्त उपबंध को उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करें।

5.3. उक्त प्रभार पारित आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे और इनकी वैधता पीपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य लेगी अर्थात् 30 सितंबर, 2020.

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन –III/4/असा./270/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd October, 2019

No. TAMP/50/2019-PPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) for fixation of wharfage for Transshipment/ Ship to Ship Transfer of LPG/ LNG at PPT Anchorage and berth on common user basis, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/50/2019-PPT

Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 10th day of October 2019)

This case relates to the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) for fixation of wharfage for Transshipment/ Ship to Ship Transfer of LPG/ LNG at PPT Anchorage and berth on common user basis.

2.1. This Authority vide its Order no. TAMP/90/2016-PPT dated 15 September 2017 had approved general revision of Scale of Rates (SOR) of PPT. The said Order was notified in the Gazette of India on 1 November 2017 vide Gazette No. 422. The Order had prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019. Subsequently, the validity of the Scale of Rates of PPT was extended till 30 September 2019 or till the effective date of implementation of the revised SOR to be notified by this Authority, whichever is earlier.

2.2. Vide the said Order dated 15 September 2017, this Authority has *interalia*, approved the wharfage for Transshipment [crude and POL] from mother to daughter vessel.

3.1. On the ground that its existing Scale of Rates does not prescribe wharfage charges for Transshipment of LPG / LNG, the PPT vide its letter No. TD/TM/GEN-241/2282 dated 5 September 2019 has filed the proposal for fixation of wharfage for Transshipment / Ship to Ship Transfer of LPG / LNG at PPT Anchorage and berth on common user basis. The main submissions made by PPT vide its letter dated 5 September 2019 are as follows:

- (i) Under the aegis of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, the consumption of LPG in India has increased over the past few years mainly due to increased LPG penetration. According to Oil Ministry, LPG penetration in the country has gone up to 88.5 per cent in 2018 as compared to 56.2 per cent in 2015.
- (ii) Owing to the surge in demand for LPG from household on the government efforts to shift to clean fuel, the LPG import reached around 13.20 million tonnes in the F.Y. 2018-19. Part of LPG requirement of east coast of India, including Odisha, is met by the LPG imported through Haldia Dock Complex, Vizag Port and Kamaraj Port, apart from movement by road tankers.
- (iii) The quantum of LPG handling and average parcel size of vessels handled in the neighboring ports are on the rise. The draft limitation at Haldia has been major bottleneck for the trade to reap the benefit of economy of scale by handling larger parcel size. Further, Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) has chalked out a plan to supply LPG to north-east states of India through Chittagong Port, Bangladesh which has also draft limitation to handle fully laden LPG vessels.
- (iv) The PPT, leveraging on its higher draft alongside berth and at anchorage, needs to take the advantage to attract the potential private and public sector oil companies to use the Port's infrastructure for LPG handling.
- (v) In this regard, the IOCL have expressed its interest to handle fully laden large size LPG vessels at PPT for lighterage operation through Ship to Ship transfer (STS) operation for discharge of LPG from mother vessel to daughter vessel. The mother vessels so lightened by transshipment in addition to daughter vessels can be handled at Haldia, Chittagong and other Ports. The copy of the letter of IOCL is furnished by PPT.
- (vi) The matter was discussed with the IOCL on 29.11.2018 to chalk out modalities of proposed transshipment / STS operation at PPT. The Chief Commissioner of Customs, Bhubaneswar has issued notification / guidelines for transshipment / STS at anchorage as well as North Oil Jetty of PPT. The copy of the said notification is furnished by PPT.
- (vii) The existing SOR of 2017 of PPT prescribes wharfage charges for transshipment of Crude and POL from mother vessel to Daughter Vessel of ₹. 7.33 per MT for foreign vessel and ₹. 4.42 per MT for coastal vessel after indexation. However, it does not specify wharfage charges for transshipment /STS of LPG/LNG.
- (viii) In order to attract / encourage cargo operation by PPT, it is proposed to charge the same rate of wharfage for transshipment /STS of LPG /LNG from mother to daughter vessels at anchorage and at berth as applicable for transshipment of Crude/ POL, and to charge vessel related charges as per extant SOR.
- (ix) Accordingly, trade circular was issued on 24.12.2018 with the approval of Chairman, PPT, allowing such transshipment operation of LPG/LNG at anchorage / North Oil Jetty. The copy of the Trade circular is furnished by PPT.

3.2. Accordingly, the PPT has sought the approval to adopt the same wharfage rate as applicable for Transshipment of Crude and POL as available in its existing SOR for Transshipment / STS operation of LPG and LNG from Mother to Daughter vessel at North Oil Jetty / Anchorage also, i.e. ₹. 7.33 per tonne for Foreign vessels and ₹. 4.42 per tonne for Coastal Vessel.

3.3. The PPT has furnished the Board Resolution no. 28/2019-20 dated 27.05.2019 approving the said wharfage rate for Transshipment / STS operation of LPG and LNG from mother to daughter vessel.

3.4. The PPT has also informed that the Port has been discussing with the potential Port users to commence the proposed Transshipment / STS operation of LPG and LNG from Mother to Daughter vessel at North Oil Jetty / Anchorage. However, such operation is yet to commence.

4. With reference to the proposal of the Port, the following position emerges:

- (i) Owing to the increase in the consumption of LPG from households on account of the Government's initiatives to shift to clean fuel, there is reported to be an increase in the import of LPG in India. The Paradip Port Trust (PPT) having a higher draft alongside berth and at anchorage wishes to attract the potential private and public sector oil companies to use the PPT's infrastructure for handling of LPG. This LPG handling is envisaged to be carried out in a manner, where fully laden large size LPG vessels will undertake lighterage operation through Ship to Ship transfer (STS) operation and discharge LPG from mother vessel to daughter vessel at PPT and thereafter, the lightened vessels will proceed to other Ports, where draft is a constraint. Since the existing Scale of Rates of PPT do not prescribe wharfage charges for Transshipment/ STS operation of LPG/ LNG from mother vessel to daughter vessel, the PPT has come up with a proposal for fixing the wharfage charges for the same.

- (ii) In this connection, the port has proposed to adopt the Wharfage charges as prescribed in its Scale of Rates for transshipment of Crude and POL from Mother Vessel to Daughter Vessel, as the wharfage charges for Transshipment/ STS operation of LPG/ LNG from mother vessel to daughter vessel.

The Scale of Rates of PPT, as approved in the year 2017, at Section 2.1 sl. No. 5, prescribes Wharfage charges for transshipment of Crude and POL from Mother Vessel to Daughter Vessel at ₹ 6.80 per MT as foreign rate and ₹ 4.10 per MT as coastal rate. Based on the enabling provisions in the Tariff Policy, 2015, (which was applicable in respect of PPT when its SOR was last fixed in the year 2017) regarding annual indexation, the prevailing Wharfage charges for transshipment of Crude and POL from Mother Vessel to Daughter Vessel is reported to be at ₹. 7.33 per MT for foreign cargo and ₹ 4.42 per MT for coastal cargo, after applying the indexation factor of 3.45% for the year 2017-18 and 4.26% for the year 2018-19, as announced by this Authority.

The said prevailing rates of ₹ 7.33 per MT for foreign cargo and ₹ 4.42 per MT for coastal cargo, are proposed to be adopted by the PPT as the wharfage charges for Transshipment/ STS operation of LPG/ LNG from mother vessel to daughter vessel. The proposal of PPT has the approval of its Board of Trustees.

- (iii) Clause 7.6.1 to 7.6.3 of the Tariff Policy, 2018, inter alia, provides that whenever a specific tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of that particular port, the concerned Major Port Trust can approach this Authority for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service by adopting the tariff and performance standards if any, fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, in consultation with the concerned users.

In the case in reference, as a marketing strategy to immediately attract/ encourage STS discharging of LPG from mother vessel to daughter vessel, the PPT has proposed to adopt the rates as prevailing in its own Scale of Rates for the transshipment of Crude and POL from Mother Vessel to Daughter Vessel.

- (iv) The PPT has reported to have issued a Trade Circular to this effect on 24 December 2018. Till date, we have not received any objection from any of the users/ user organisations on the Trade Circular issued by the PPT for levy of the charges by PPT for STS discharging of LPG from mother vessel to daughter vessel. Clause 4.4 of the Tariff Policy, 2018, provides that incase there are no objections from users for a proposal or a case, this Authority need not organize any joint hearing. In the case in reference, since there are no objections from the users/ user organizations till date, after issue of the Trade Circular by PPT, no joint hearing was set up on the matter in reference.

- (v) Considering that the proposed wharfage charges for Transshipment/ STS operation of LPG/ LNG of ₹ 7.33 per MT for foreign cargo and ₹ 4.42 per MT for coastal cargo, as proposed by PPT is an adoption of the existing wharfage charges prescribed for Transshipment of crude and POL at PPT and since the proposed charges has the approval of the Board of Trustees of PPT and also since we have not received any objections from any of the users/ user organization regarding levy of the charges by PPT, this Authority is inclined to approve the rate of ₹ 7.33 per MT as foreign rate and ₹ 4.42 per MT as coastal rate, as the wharfage charges for Transshipment/ STS operation of LPG/ LNG, as proposed by the PPT.

- (vi) The port has not quantified the revenue impact due to implementation of proposed wharfage rate for Transshipment / STS operation of LPG/LNG. However, during the last general revision of tariff of PPT

in September 2017, there was a revenue gap to the tune of ₹ 25.01 crores, which has been left uncovered by the Port, then. The additional revenue if any, arising out of the levy of wharfage rate for Transshipment / STS operation of LPG/ LNG approved, is anticipated to get subsumed in the revenue gap.

- (vii) The validity of the existing Scale of Rates of PPT has been extended upto 30 September 2020 vide a separate Order no. TAMP/90/2016-PPT dated 10 October 2019. During the next review of the tariff of PPT, the PPT is advised to work out wharfage rate for Transshipment/ STS operation of LPG/ LNG, based on the stipulation contained in clause 7.6.1 of the Guidelines. Till the review of the existing Scale of Rates of PPT, the rate approved now, will continue to be levied by PPT and its validity shall remain co-terminus with the extended validity of the General SOR of PPT.
- (viii) Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, this Authority grants approval for levy of wharfage rate for Transshipment / STS operation of LPG/ LNG prospectively after the expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

5.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, the introduction of the following new sl. No. 5(a) in the Wharfage schedule at Chapter-II under 2.1 - Wharfage charges, in the existing Scale of Rates of PPT is approved:

“2.1 Wharfage charges:

Sl. No.	Description of goods	Rate per MT or part thereof (₹)	
		Foreign rate	Coastal rate
5(a)	Transshipment/ STS operation of LPG/LNG from mother vessel to daughter vessel at North Oil Jetty / Anchorage	7.33	4.42

5.2 The PPT is advised to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

5.3. The said charges shall come into effect after the expiry of 30 days from the date of Notification of the Order passed in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus with the validity of the existing Scale of Rates of PPT i.e. upto 30 September 2020.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./270/19]